1	2	3	4
Jodhpur	89	280	205
Kota	..	341	190
Nagpur	149	232	288
Pali	114	34	65
Sawai Madhopur	28	684	81
Sikar	95	179	139
Sirohi	68	147	..
Tonk	46	213	125
Udaipur	375	739	506
TOTAL	2120	10180	4474

HUDCO Loan to Rajasthan

560. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the amount of loans extended to Rajashthan by the HUDCO during the last three years;

(b) the amount of loans repaid so far; and

(c) the number of schemes received from the State so far and still pending with HUDCO for clearance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) The details of the loan sanctions (including land Acquisition and operational finance) in the State of Rajasthan by HUDCO during the last 3 years are as under:—

Year	Loan Amount(Rs. in crores)
1986-87	16.84
1987-8	28.61
1988-89	31.14

(b) As against a cumulative loan amount of Rs. 231.63 crores upto 31.3.89 since inception, a repayment amounting to Rs. 88.87 crores have been received.

(c) Seven Schemes (for conventional projects) for a loan amount of Rs. 7.09 crores are in the pipeline.

Laying of Sewerage in Pitampura

561. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the scheduled dates of completion of the work of laying peripheral sewerage upto Avantika Pumping Station from Pocket IV in Pritampura (outer Ring Road near Mangolpuri;

(b) whether there was any delay in the completion of this work;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the dates on which these works were warded to contractors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) 19.3.86 & 20.10.1988.

(b) Yes, Sir.

(c) (i) Sewer is very deep, i.e. to be laid at a depth of 6.5 Mtr. to 7.5 Mtr. which required huge excavation whereas the working space available was very limited due to existing structures and passing through congested area like Mangolpuri resettlement colony. The workability thus got affected.

(ii) Some electric poles falling in the alignment were required to be shifted by DESU.

(iii) Disruption of work by Heavy rains in 1988.

(d) 10-12-85 and 21-4.1988.

एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० को हुई हानि

562. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के भारतीय उर्वरक निगम और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन निगमों की अलग-अलग प्रति वर्ष कितना-कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन एककों को उबारने के उद्देश्य से घाटे के कारणों का पता लगाने और इस समस्या का समाधान करने के उपायों को सुझाने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अब प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो किस-किस जांच दल ने क्या-क्या रिपोर्ट दी और ये रिपोर्टें सरकार को कब-कब प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा उनके अनुसार अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : (क) और (ख) जी, हां, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ० सी० आई०) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच० एफ० सी०) द्वारा उठाई गई हानियां नीचे दी गई हैं :–

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	एफ सी आई	एच एफ सी
1986–87	105.91(*)	86.02
1987–88	115.41(**)	104.34
1988–89	151.00 (अनंतिम)	159.30 (अनंतिम)

(*) पूर्व अवधि समंजन के पश्चात् शुद्ध हानि 102.53 करोड़ रुपए थी।

(**) पूर्व अवधि समंजन के पश्चात् शुद्ध हानि 42.67 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) सरकार ने इन दो कम्पनियों की समस्याओं की जांच करने और उसके निष्पादन में सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियां स्थापित की। इन समितियों के ब्यौरे, विचारार्थ विषय तथा उनकी सिफारिशों के संक्षिप्त विवरण अनुपत्र में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 150, अनुपत्र सं० 23]

एच० एफ० सी० के नामरूप/बा–और ।।, बरौनी और दुर्गापुर के चालू एककों तथा इसकी हल्दिया उर्वरक परियोजना का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने के लिए सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। सलाहकारों की रिपोर्टें प्राप्त हो हो गयी है। परन्तु निवेश निर्णय नहीं लिए गए हैं।

एफ सी आई के मामले में रामागुण्डम तथा तलचर में स्थित कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्रुप कोप्पर्स द्वारा किया गया था। उनकी सिफारिशों के आधार पर दोनों संयंत्रों के पुनर्वास की योजनाएं तैयार की गयी हैं। शुरुआत के लिए यह निर्णय किया गया है कि रामागण्डम एकक की पुनर्वास योजना के चरण–। को कार्यान्वित किया जाए।